



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2636]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939

No. 2636]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/ BHADRA 22, 1939

## भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2017

**का.आ. 3012(अ).**—भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम [फेम-इंडिया स्कीम] जो भारी उद्योग विभाग द्वारा का.आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 को अधिसूचित की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:—

- (1) अनुबंध 7, तालिका 7.2: पीएचईवी तथा बीईवी के लिए इलेक्ट्रिकल रेंज समाप्त कर दी गई है।
- (2) अनुबंध 7, तालिका ए 7.3: बस विद्युत ऊर्जा खपत मानदंड निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है:

#### तालिका ए 7.3: बस विद्युत ऊर्जा खपत मानदंड

प्राचल	बीईवी
अधिकतम ऊर्जा खपत (किलोवाट घंटा/100 किमी)	175 से कम

- (3) अनुबंध 13 के अंतर्गत: निम्नलिखित नई तालिका 8 जोड़ी जाती है:

#### तालिका 8 : इलेक्ट्रिक बस

बस	सीएमवीआर की श्रेणी	प्रोत्साहन स्तर 1	प्रोत्साहन स्तर 2
पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस	एम2 एवं एम3	क्रय लागत का 60% अथवा ₹ 85 लाख (जो भी कम हो) यदि कम से कम 15% स्थानीकरण हासिल किया हो।	क्रय लागत का 60% अथवा ₹ 1 करोड़ (जो भी कम हो) यदि कम से कम 35% स्थानीकरण हासिल किया हो।

**टिप्पणी :**

1. प्रोत्साहन राशि का निर्णय क्रेता द्वारा जारी किए गए आपूर्ति आदेश के आधार पर लिया जाएगा। क्रेता को आपूर्ति का अंतिम निर्णय विधिवत निविदा प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् लेना होगा।
2. प्रोत्साहन राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसकी अदायगी तीन वर्षों में की जानी होगी। पहली किस्त आपूर्ति आदेश/संविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।
3. प्रोत्साहन, क्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता अथवा विनिर्माणकर्ता को उनके बीच परस्पर सहमति के आधार पर दिया जाएगा।
4. स्थानीकरण का परिकलन फैक्ट्री कीमत के आधार पर किया जाएगा।
5. मूल उपकरण विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता को स्थानीकरण सामग्री के बारे में स्वतः प्रमाण पत्र जारी करना होगा; तथापि, विशेषीकृत विशेषज्ञ एजेन्सियों से स्वप्रमाणन को सत्यापित कराने का अधिकार भारी उद्योग विभाग के पास रहेगा।
6. अतिरिक्त वित्तीय सहायता क्रेता और मूल उपकरण विनिर्माता/विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बीच संविदा सहमति के अनुसार ईवी बसों के बड़े की खरीद के लिए कुल अर्हक मांग प्रोत्साहन के 10% तक चार्जिंग उपकरणों की खरीद हेतु राज्य परिवहन उपक्रमों/नगर-निगमों को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. अतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम] जो का.आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 को अधिसूचित की गई थी, तदनुसार संशोधित की जाती है।

[फा. सं. 2(2)/2016-एनएबी-II(ऑटो)]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2017

**S.O. 3012(E).**—In partial modification of the Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India [FAME-India Scheme] which was notified by the Department of Heavy Industry vide S.O. 830(E) dated 13<sup>th</sup> March, 2015, the following amendments are made with immediate effect:—

- (1) Annexure-7, Table 7.2: Electrical Range for PHEV and BEV stands deleted.
- (2) Annexure-7, Table A 7.3 : Bus Electric Energy Consumption criteria, is replaced by the following Table:

**Table A 7.3: Bus Electric Energy Consumption criteria**

Parameter	BEV
Maximum Energy Consumption (kwh/100 Km)	Less than 175

- (3) Under Annexure 13: following New Table 8 is inserted:

**Table 8 : Electric Bus**

Bus	Category of CMVR	Incentive Level 1	Incentive Level 2
Fully Electric Bus	M2 & M3	60% of purchase cost or Rs. 85 Lakh (whichever is lower) In case localization of minimum 15% is achieved.	60% of purchase cost or Rs. 1 Crore (whichever is lower) In case localization of minimum 35% is achieved.

**Notes :**

1. Incentive amount will be decided based on the supply order issued by the purchaser. Purchaser has to finalize the supply after following due tendering process.
2. Incentive amount will be disbursed in three equal installments to be paid in three years. First instalment will be released after conclusion of supply order/contract.
3. Incentive shall be disbursed either to a purchaser or to a supplier or manufacturer based on their mutual consent.
4. Localization will be calculated based on Ex-Factory Price.
5. OEM/Supplier to issue self-certification about localization contents; however, DHI retains the right to get the same validated from specialized expert agencies.
6. An additional financial assistance shall be provided towards purchase of charging equipment up to 10% of total eligible demand incentive for purchase of fleet of EV buses as per the contract agreement between purchaser and OEM/manufacturer/Supplier to State Transport Undertakings/Municipal Corporations.

2. Therefore, FAME-India [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid&) Electric Vehicles in India] scheme notification *vide* S.O. 830(E) dated 13<sup>th</sup> March, 2015 stands amended accordingly.

[F. No. 2(2)/2016-NAB-II(Auto)]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.